

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-79/2022-23

सरकार

-बनाम-

जमरुद्दीन आलम

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -2899/अ० शा० दिनांक - 07.10.2022 के द्वारा वादिनी श्रीमती अरुनिमा एक्का पति-अनिष टोप्पो सा०-बहोरनपुर जिला-हजारीबाग अंचलाधिकारी सिसई जिला-गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं०-83/2022 दिनांक-27.07.2022 धारा-379/411 भा० द० वि० 21 खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम-1957 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम-2017 के तहत अवैध रूप से कोयल नदी से बालू का उत्खनन कर व्यवसाय के उद्देश्य से ट्रैक्टर में लोड करने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH08E- 8881, के मालिक जीमरुद्दीन आलम पे०-मो० हसन सा०-शिवपुर पो०-आंजन थाना-गुमला जिला-गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा लिखित बहस समर्पित किया गया है, परन्तु उत्तरवादी के द्वारा सुनवाई के दौरान अवैध रूप से खनिज का परिवहन करने से संबंधित कोई वैध कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहे।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि श्रीमती अरुनिमा एक्का पति-अनिष टोप्पो सा०-बहोरनपुर जिला-हजारीबाग अंचलाधिकारी सिसई के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर व्यवसाय करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH08E- 8881, के मालिक जीमरुद्दीन आलम पे०-मो० हसन सा०-शिवपुर पो०-आंजन थाना-गुमला जिला-गुमला के विरुद्ध बालू का उत्खनन कर परिवहन कर व्यवसाय करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with

direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहनों के द्वारा अबन्दोबरत नदी घाट से बालू का उठाव कर एवं अवैध रूप से बालू का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH08E- 8881, को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

26.12.21
उपायुक्त,
गुमला

26.12.21
उपायुक्त,
गुमला